राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक : 15.02. 2019
स्थान –होटल रेडिशन ब्लू, रांची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड के 66 वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत
Minutes of the 66th Quarterly Meeting of SLBC, JHARKHAND

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 66वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन दिनांक 15.02.2019 को होटल रेडिसन ब्लू , रांची में किया गया|

इस बैठक के आरम्भ होने के पूर्व एस.एल.बी.सी के मुख्य प्रबंधक श्री दीप शंकर ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को जानकारी देते हुए कहा कि बैठक के लिए एस.एल.बी.सी. द्वारा अजेंडा की तैयारी में विभिन्न विभागों से मिले सुझाव एवं बैंकों के सहयोग से विभिन्न डाटा के रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने का काफी प्रयास किया गया है | इस प्रयास के बावजूद इसमें कुछ कमी रह जाने की बात उन्होंने कही |

इस सभा के आरम्भ में SLBC के महा-प्रबंधक श्री चंद्रशेखर सहाय मंचासीन सभी गण-मान्य एवं सभा में उपस्थित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से आये वरिष्ट अधिकारियों तथा विभिन्न बैंकों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया | इसके पश्चात् उन्होंने MSME Support and Outreach Program के तहत भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार चयनित जिलों बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी एवं गोड्डा को विभिन्न योजनाओं के लिए दिए गए टारगेट प्राप्त करने के लिए कैम्पों के सफल आयोजन के लिए इन जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधकों, इस कार्यक्रम से जुड़े सरकारी विभागों के अधिकारी गण एवं बैंकों को धन्यवाद् दिया जिनके सहयोग से अभी तक 63 केम्पों का आयोजन किये जा चुके है एवं दिए गए टारगेट पर 92% की उपलब्धि भी प्राप्त की जा चुकी है | उन्होंने इस कार्यक्रम के समाप्ति तक निश्चित तौर पर 100% की उपलब्धि प्राप्त कर लेने का आशा व्यक्त किया |आगे उन्होंने बतलाया कि बैंकों द्वारा विभिन्न मानकों में अच्छा प्रदर्शन रहा है | सी.डी. रेशियो में सुधार हुआ है और रेगुलेटरी मानकों जो 60% निर्धारित है के विरुद्ध 60.04 % रहा है | उन्होंने इसे और बेहतर करने का बैंकों से आह्वान किया | कुछ विशेष योजनायें जैसे कृषि ऋण, पी.एम्.इ.जी.पी., प्रधानमंत्री शहरी आवास ऋण के कार्यान्वयन में बैंकों का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहने की

बात कहते हुए इन सब योजनाओं में सभी बैंकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया | बैंकों में बढ़ते NPA की स्थिति पर उन्होंने चिंता जाहिर की | उन्होंने NPA खातों के रिकवरी में सहयोग करने का सरकार के सम्बंधित विभागों से निवेदन किया | अंत में उन्होंने सभा को आश्वासन देते हुए कहा कि SLBC आगे भी राज्य के विकास में अपना सक्रिय भागीदारी दृढ़ता से जारी रखेगा |

महाप्रबंधक SLBC के संबोधन के पश्चात् मंच में उपस्थित सभी सम्मानित उच्च पदाधिकारियों का पुष्प गुच्छ दे कर स्वागत किया गया |

नाबार्ड के CGM श्री ए. के. पाढ़ी अपने वक्तब्य में बैंकों के CD रेशियो में सुधार पर प्रशन्नता जाहिर करते हुए कहा कि आगे भी इस स्थिति को बनाये रखते हुए और बेहतर करने का प्रयास किए जाने की आवश्यकता है | कृषि ऋण का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में कृषि ऋण का प्रतिशत राष्ट्रीय बेंचमार्क 18% से पीछे है और इसमें बैंकों को काफी काम किये जाने की आवश्यकता है | राज्य में 50% से भी कम किसानो को KCC प्राप्त है जिसे 100% का लक्ष्य रखते हुए हरेक पात्र किसानो को KCC दिए जाने की आवश्यकता की बात कही | उन्होंने कहा कि बैंकों के शाखा-वार ADS स्कीम की संभावना को ध्यान में रखते हुए जानकारी बैंकों को दे दी गई है | इस योजना के तहत कृषक को ऋण देने के साथ ही उनके कार्य की विशेष निगरानी किये जाने के आवश्यकता की बात कही | इस कार्यक्रम के द्वारा दुग्ध विकास, सुकर पालन, बकरी पालन, मत्स पालन, मधुमखी पालन एवं लाह उत्पादन गतिविधियों का मूल रूप से विकास किया जाना है जिसके लिए नाबार्ड के पास 400 करोड़ रूपये की सहयता राशी उपलब्ध है | बैंक इन चुने गए गतिविधियों में ऋण देकर अपने कृषि ऋण के आंकड़ो को बढ़ा सकते हैं | आगे उन्होंने कहा कि भारत सरकार के कई ऐसे स्कीम हैं जिसमे सब्सिडी उपलब्ध है परन्तु बैंकों की उदासीनता के कारण इन सब्सिडी प्राप्त स्कीम में पुर्णतः कार्य नहीं किया जा रहा है | विशेषकर दुग्ध उत्पादन गतिविधि के लिए 6.6 करोड़ रूपये वर्ष 2018-19 के लिए सब्सिडी उपलब्ध है और अभी तक बैंकों द्वारा मात्र 30% का ही सब्सिडी क्लेम किया गया है | वित्त समावेशन के अंतर्गत उन्होंने कहा कि उनके विभाग द्वारा संचालित 7 जिलों के प्रत्येक SHG ग्रुप के साथ उनके मेम्बरों का भी SHG पोर्टल में प्रोजेक्ट ESHAKTI के अंतर्गत नामांकन होना आवश्यक है जिससे ग्रुप से सम्बंधित सारी जानकारी SHG के पोर्टल में उपलब्ध हो सकेगी | भारत सरकार के निर्देशानुसार हरेक SHG सदस्यों का बैंक में एक बचत खाता होना, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जीवन बीमा पालिसी एवं अटल पेंसन का खोला जाना आवश्यक है | अंत में उन्होंने नाबार्ड द्वरा सहायता दिए जाने वाले फारमर्स प्रोड्यूसर आर्गेनाईजेशन की संछिप्त जानकारी दी |

श्री शंकर प्रसाद, महा-प्रबंधक, बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय ने अपने संबोधन में कहा कि DFS के निगरानी में तीन विशेष कार्यक्रम चलाई जा रही है जिसमे प्रथम, राज्य के सभी किसानो के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना है | इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि झारखण्ड

राज्य में 39 लाख किसान हैं जबकि SLBC को बैंकों द्वारा प्राप्त आंकड़ो के अनुसार 17.44 लाख किसानो के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है | जिन किसानो के पास KCC नहीं है उन्हें चिन्हित कर KCC लेने के लिए प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया | इसके लिए स्वयं सेवी ग्रुप एवं बैंकों के बी.सी. से भी सहायता लिए जाने की बात कहा | आगे उन्होंने झारखण्ड सरकार से निवेदन करते हुए कहा कि इस कार्य को और अधिक कारगर बनाने के लिए प्रखण्ड स्तर पर कार्यरत कृषि विभाग एवं भू-राजस्वा विभाग को निर्देश दिया जाय कि इस कार्य में बैंकों को उनके विभाग से सम्बंधित आवाश्यहक सहायता उपलब्ध कराएं | 100 % Saturation की स्थिति पाने के लिए जितने भी संभावनाएं है, इस्तेमाल में लाना पड़ेगा | MSME support & Outreach Program के तहत राज्य के चयनित चार जिलों को दिए गए टारगेट के विरुद्ध उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धि में उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की | Financial Inclusion Initiative कार्यक्रम के तहत बैंकों द्वारा जन-धन खोले गए खातों की संख्या पर भी प्रसन्नता जाहिर की परन्तु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्राप्त उपलब्धि पर उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य से राज्य पीछे रह गया है | उन्होंने बैंकों से पूरा प्रयास करने को कहा ताकि मार्च 2019 तक 100% का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके |

इनके संबोधन के पश्चात SLBC के मुख्य प्रबंधक ने राज्य सरकार के कृषि विभाग से निवेदन करते हुए कहा कि पूर्व में भी बैंकों द्वारा आग्रह किया जाता रहा है कि जिन योग्य किसानो का किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, उसका ब्योरा बैंकों को मुहैया कराएं जाएँ ताकि उन्हें भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा सके, परन्तु अभी तक विभाग द्वारा यह ब्योरा अप्राप्त है |

भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक श्री संजीव दयाल सभा में उपस्थित सभों का अभिनन्दन करने के पश्चात अपना अभिभासन आरम्भ करते हुए बैंकों के जमा एवं ऋण में वर्ष से वर्ष एवं तिमाही से तिमाही वार इस तीसरे तिमाही में हुए प्रगति में प्रसन्नता जाहिर की | उन्होंने सी.डी. रेसिओ के 60% पार कर लेने पर कहा कि ये बैंकिंग कार्य में प्रगति की एक अच्छी निशानी है | वार्षिक ऋण योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि SME के अंतर्गत अच्छा कार्य हुआ है परन्तु इसके विपरीत कृषि ऋण में वांछित प्रगति नहीं हुई है | बैंको में सकल NPA की वृधि में उन्होंने चिंता जाहिर की | आगे उन्होंने कुछ बैंकों द्वारा SLBC को गलत डाटा दिए जाने पर कहा कि इससे SLBC को डाटा के कम्पायलिंग में काफी कठिनाइयाँ होती है साथ ही इससे पुरे राज्य का डाटा भी गलत हो जाता है जिसके चलते राज्य के विकास से सम्बंधित विभिन्न योजना का रूप रेखा सही नहीं बन पता है | SLBC से उन्होंने गलत डाटा देने वाले बैंको से स्पस्टीकरण मांगने की बात कही | अगर किसी बैंक द्वारा स्पस्टीकरण नहीं दिया जाता है तो उनके उच्च अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन कर स्पस्टीकरण माँगी जाय | इस बैठक में RBI के प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे | इसके पश्चात उन्होंने अगले तिमाही अजेंडा में कुछ बातों का समावेश किये जाने की बात कही जिनमे मुख्य डिजिटल

एक्टिविटी, अवैध कंपनियों द्वारा अवैध जमा संग्रहन, बैंकों से सम्बंधित साईबर अपराध एवं ऋण से सम्बंधित फ्रॉड | इन्होने बैंकों से कहा इस तरह की कोई भी अपराधिक घटना नजर में आती है तो इसकी जानकारी SLBC को दी जानी है | आगे उन्होंने कहा कि SLBC द्वारा बैंकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 5000 की जनसंख्या से अधिक के ग्राम में पूर्ण रूप से BC एजेंट की बहाली का प्रमाण पत्र RBI को दिया जा चूका है | इसी तर्ज में 2000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामो का भी BC एजेंट द्वारा कभर करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही | उन्होंने राज्य सरकार द्वारा नवम्बर 2018 में सुखाड़ पर जारी किये गए नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में 18 जिलों के 129 ब्लोक में सुखाड़ घोषित किया गया है | RBI के निर्देशानुसार जिन सुखाड़ घोषित जगहों में 33% या अधिक फसल नुकसान हुआ है, राहत के लिए SLBC द्वारा पहल किया जाना है, लेकिन राज्य में स्थानवार नुकसान का प्रतिशत राज्य कृषि विभाग द्वारा SLBC के बार-बार मांगे जाने पर भी अभी तक अप्राप्त है | उन्होंने राज्य सरकार के कृषि विभाग से इसकी जानकारी तुरंत SLBC को मुहैया कराये जाने की बात कही | FLC के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि कई FLC अभी तक बैंकों के अपने आन्तरिक स्थाई कर्मचारियों द्वारा ही चलाई जा रही है जबकि इसके लिए कौन्सलर की नियुक्ति की जानी है | झारखण्ड ग्रामीण बैंक एवं राज्य सहकारी बैंकों द्वारा चलाये जा रहे FLC के सम्बन्ध में कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक इनमे आंतरिक अधिकारियों द्वारा FLC चलाये जा रहे हैं | इसकी पूर्ण जानकारी उन्होंने नाबार्ड से मांगी | इसके पश्चात उन्होंने डेडिकेटेड सर्टिफिकेट अधिकारी से सम्बंधित मुद्दे पर जिक्र करते हुए जानना चाहा कि बैंकों में NPA बढ़ रही है लेकिन इन अधिकारियों की नियुक्ति के मुद्दे को SLBC के अजेंडा से बाहर कर लेने का क्यों प्रस्ताव रखा गया है | अंत में उन्होंने बैंकों में PMEGP के काफी आवेदनों के पेंडिंग रहने का जिक्र करते हुए LDM से इसपर ध्यान देने की बात कही |

भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक के संबोधन समाप्त होने के पश्चात श्री दीप शंकर ने उन्हें जानकारी देते हुए कहा कि SLBC द्वारा 2000 से अधिक एवं 5000 से कम तक के जनसंख्या वाले ग्रामो में BC एजेंट द्वारा अच्छादन पर कार्य किया जा रहा है | 2000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में भी ये कार्य पूर्ण होते ही RBI को प्रमाण पत्र मुहैया करा दिया जायेगा | डेडिकेटेड सर्टिफिकेट अधिकारी के नियुक्ति के मुद्दे को SLBC के अजेंडा से निकाल लिए जाने के प्रस्ताव का कारण बतलाते हुए कहा कि इनके administrative खर्च वाहन करने को बैंकों द्वारा असहमति जाहिर किया गया है | इस सम्बन्ध में अन्य राज्य किस तरह कार्य कर रहे है इसकी जानकारी अन्य राज्यों से लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है |

श्री सत्येन्द्र सिंह, सचिव योजना एवं व्यय, झारखण्ड सरकार ने अपना संबोधन आरम्भ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानो को उनके बैंक खातो के माध्यम से DBT द्वारा रकम देना है | इसके लिए आवश्यक है हरेक किसान का अपना बचत खाता तथा आधार कार्ड हो एवं आधार उनके खाते में जुड़ा हो तथा मैपिंग किया गया हो | ये सभी कार्य पूर्ण रूप से सही-सही किया जाना आवश्यक है ताकि समय पर एवं सही किसान को

उनको मिलने वाली राशि मिल सके | राज्य सरकार द्वारा भी किसानो को दिए जाने वाले मोबाइल, कृषि यंत्र एवं कृषि से सम्बंधित अन्य खर्च सामान के रूप में न देकर उनके खातों के माध्यम से DBT द्वारा सीधे रकम मुहैया कराई जाएगी | बैंकों द्वारा शाखा खोले जाने विषय पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में बैंकों एवं RBI द्वारा मिलकर 137 ऐसे स्थानों (ग्राम) का चयन किया गया था जहाँ 2017 तक बैंकों की शाखाएं खोली जानी थी एवं बैंकों की सहमति से बैंकों को शाखा खोलने के लिए आवंटन भी कर दिया गया था | लेकिन अभीतक मात्र 35 शाखाएं ही चयनित जगहों में खुल पाए हैं | आगे उन्होंने कहा कि BC द्वारा कवर किये गए क्षेत्र को बैंकिंग सेवा प्राप्त क्षेत्र माना जाता है | लेकिन इससे चयनित स्थानों में बैंक की शाखा खोला जाना स्थगित नहीं किया जा सकता है | अतः बैंक सुनिश्चित करें कि इन चयनित स्थानों में निर्धारित बैंक की शाखा अवश्य खुले इसके लिए राज्य सरकार द्वारा शाखा खोलने के लिए मकान एवं सुरक्षा दिलाये जाने की बात कही | अंत में उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा राज्य के पलामू जिले में बैंकों की 6 शाखाएं खोले जाने का निर्देश है जिसके तहत निर्धारित 4 स्थानों में बैंकों की शाखाएँ खुल चुकी हैं | शेष 2 स्थल रामगढ़ एवं नगर उटारी में शाखा खोला जाना बाकी रह गया है |उन्होंने SBI से कहा कि मार्च 2019 तक नगर उटारी एवं रामगढ़ में अपनी शाखाएं खोलना सुनिश्चित करें |

भारत सरकार DFS विभाग के संयुक्त सचिव **श्री मदनेश मिश्रा** अपना वक्तव्य आरम्भ करते हुए MSME support & outreach program के अंतर्गत झारखण्ड में अबतक किये गए कामो की प्रसंशा की | इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के चयनित 104 जिलों में से झारखण्ड राज्य के 4 जिलों का चयन किया गया है | आगे उन्होंने कहा कि CD ratio में सुधार करते हुए , महिलाओं एवं अल्प संख्यक वर्ग को ऋण तथा शिक्षा एवं आवास के लिए ऋण मुहैया कराने में और प्रयास करने की जरुरत है | उन्होंने सचिव योजना एवं व्यय झारखण्ड सरकार के वक्तब्य का संदर्व लेते हुए आधार कार्ड के महत्वा की चर्चा की | आगे उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन समिति का गठन किया जाना है जिसकी बैठक कम से कम छह: माह में एक बार किया जाना है जिसमे राज्य में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हुए प्रगति की समीक्षा की जानी है | इस समिति का गठन झारखण्ड में अभी तक नहीं हो पाया है | DFS द्वारा झारखण्ड राज्य के पलामू जिले में 6 शाखाएं खोले जाने के लिए आवंटित किया गया है जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा 4 शाखाएं खोल लिए गए हैं | बाकी बचे दो शाखाओं को भी मार्च 2019 तक खोल लेना है ताकि इसका प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय को समय पर सौपा जा सके | आगे उन्होंने कहा कि 5000 से अधिक जनसंख्या वाले सारे ग्रामो में BC तो लगाये जा चुके हैं लेकिन प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार काफी BC ऐसे हैं जिनके द्वारा माह में 50 से भी कम लेन-देन किया जाता है | शाखाओं को उनके

BC के कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है साथ ही बैंक के एक उच्च अधिकारी के द्वारा भी समय-समय पर इनके कार्य की वास्तविकता की जाँच की जानी चाहिए | इस विषय में उन्होंने अगले SLBC के तिमाही बैठक में BC द्वारा किये जा रहे कार्य के डाटा के साथ चर्चा करने की बात कही | आगे उन्होंने MSME support एवं Outreach Program की चर्चा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान 59 मिनट में PSB online लोन आवेदन को In principle approval कर बैंकों को भेजे गए परन्तु काफी आवेदन बे-बुनियाद कारणों से निरस्त कर दिए गए | आवेदक द्वारा दिए विभिन्न जानकारी के आधार पर इसके online प्लेटफोर्म द्वारा लोन की आवश्यकता की गणना कर चयनित आवेदन को In principle approval कर प्लेटफार्म के माध्यम से सम्बंधित बैंकों को आगे की कार्यवाही एवं अंतिम स्वीकृति के लिए प्रेषित कर दिया जाता | अंतिम स्वीकृति के दौरान अधिकतर आवेदन बैंकों द्वारा विभिन्न कारण बतला कर निरस्त कर दिये जाते हैं | उन्होंने LDM को निर्देश देते हुए कहा कि वे जानकारी इकट्ठा करें कि उनके जिलों मे कितने In-principle sanctioned आवेदन प्राप्त हुए एवं उनमे से कितने आवेदन निरस्त किये गए | आगे उन्होंने digital transaction को बढ़ावा देने पर चर्चा करते हुए कहा कि लोगों को इसके लिए प्रेरित करें | उन्होंने SLBC से मार्च माह की समाप्ति के बाद digital transaction बढाने के लिए कैम्प आयोजन कर लोगों को digital transaction करने के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम करने की बात कही | अंत में उन्होंने बैंकों से कहा वर्तमान वित्त वर्ष समाप्ति में डेढ़ माह बाकी रह गये है और इस दौरान रह गए कमियों के कारणों पर मंथन कर कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाय ताकी अगले वित्त वर्ष में और बेहतर कार्य किया जा सके |

व्यवसाय सत्र (Business Session) :

मुख्य प्रबंधक, SLBC, श्री दीप शंकर द्वारा व्यवसायिक सत्र की कार्यवाही शुरूवात करते हुए सबसे पहले दिनांक 07.12.2018 को आयोजित 65वीं SLBC बैठक के कार्यवृत की संपुष्टि सभा द्वारा करायी गयी |

तत्पश्चात श्री दीप शंकर द्वारा एसएलबीसी की 66 वीं बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित एजेंडा क्रमवार निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :

<u>अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदात ऋण</u>

श्री मदनेश मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्त सेवाएँ विभाग भारत सरकार ने झारखण्ड राज्य में बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को दिए गए ऋण निर्धारित मानक से कम होने की बात कही | इसमें बैंकों द्वारा सुधार लाने की आवश्यकता है | **(Action : सभी बैंक)**

सभी बैंको के महत्वपूर्ण संकेतक

इस विषय पर सभा को बताया गया कि Y-o-Y basis पर की जाने वाली तुलना के साथ साथ SLBC द्वारा राज्य में पिछले तिमाही की तुलना में हुई वृद्धि/ह्रास की जानकारी भी देने का प्रयास किया गया है और अगली बैठक से इसकी रिपोर्टिंग में और भी आवश्यक संशोधन करने का प्रयास किया जायेगा | महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समुदायों को दिये जाने वाले ऋण से संबंधित रिपोर्टिंग में कई बैंको द्वारा काफी variation किये जाने की तरफ सभा का ध्यान आकृष्ट कराया गया साथ ही INDUSIND बैंक जिनके कारण कई आंकड़ों में त्रुटी आई थी उनको सभा के माध्यम से आंकड़ों को त्रुटिहीन रखने का आग्रह किया|और सभी से इस पर ध्यान देने की अपील की गई | **(Action: SLBC, सभी बैंक)**

वार्षिक ऋण योजना के आधार पर वर्ष 2018-19 की उपलब्धि की समीक्षा

इस विषय पर मुख्य प्रबन्धक श्री दीप शंकर ने जानकारी देते हुए बतलाया कि reporting quarter के दौरान बैंको ने ACP target के विरुद्ध लगभग 70 % achievement कर लिया है | राज्य का CD ratio इस तिमाही 60% के मानक को पार कर गया है। सभा को बताया गया कि पिछले quarter के दौरान राज्य में बैंको द्वारा दर्ज की गयी incremental CD ratio 97.62 % है | कई sectors में बैंको द्वारा reporting में की गयी खामियों की चर्चा की गयी और उनसे आने वाले समय में reporting में आवश्यक सुधार किये जाने का आग्रह किया गया | सभा को बैंक की शाखाओं की संख्या के आधार पर की गयी रैंकिंग की जानकारी दी गयी | राज्य में बैंकों के Overall प्रदर्शन के आधार पर दो सर्वश्रेष्ठ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया।

(Action: सभी बैंक एवं SLBC)

कृषि ऋण एवं किसान क्रेडिट काई

इस पर चर्चा करते हुए सभा को बताया गया कि कृषि क्षेत्र में वर्तमान तिमाही तक इस वित्तीय वर्ष में 2813.89 करोड़ रु का संवितरण हुआ है जो कि कुल लक्ष्य का 33% ही है, यह अतिचिंतनीय है। इसमें KCC में रु 1747.14 करोड़ का संवितरण हुआ है। यह आंकड़ा उत्साहवर्धक कतई नहीं है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा KCC SATURATION का अभियान चलाया जा रहा है। सभी बैंक से आग्रह किया गया है की राज्य के सभी योग्य किसानों को KCC के अंतर्गत कवर करने का संकल्प लेते हुये अभियान के समयसीमा के अंतर्गत SATURATION सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य में इस वर्ष कुल 2813.89 करोड़ के कृषि ऋण वितरण के बावजूद कृषि ऋण के कुल o/s में रु 881.75 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गयी है, जिससे reporting की accuracy पर संदेह होता है |श्री दीपशंकर ने बताया की आरबीआई के नए निर्देशानुसार कृषि ऋण में collateral security की बाध्यता की सीमा को 1.00 लाख से बढ़ा कर 1.60लाख कर दिया गया है।इस संशोधन का लाभ लेते हुये वैसे योग्य पुराने केसीसी जिनका लिमिट समुचित collateral के अभाव में 1.00 लाख से नहीं बढ़ाया जा सका है उनमें पात्रता होने पर सीमा 1.60 लाख की जा सकती है। सभी बैंक से आग्रह किया

गया की नए नियमों का अवलोकन करते हुये कृषि ऋण में आशातीत वृद्धि दर्ज की जा सकती है।डेयरी के अंतर्गत लंबित आवेदनो को तुरंत निष्पादित करते हुए योजना अंतर्गत दिये जा रहे अनुदान के लिए पोर्टल पर तुरंत आवेदन करने को कहा गया।नाबार्ड के सीजीएम श्री पाढ़ी ने कहा कि अगर **एरिया बेस्ड स्कीम** को सही से लागू किया जाय तो कृषि ऋण में वृद्धि दर्ज कि जा सकती है। श्री दीपशंकर द्वारा एलडीएम से आग्रह किया गया कि **एरिया बेस्ड स्कीम** के प्रदर्शन को DCC में एक agenda के रूप में शामिल करने को कहा।

(Action: बैंक एवं एलडीएम)

<u>राज्य में घोषित सुखाड़ के तहत affected किसानों को Relief Measures प्रदान करना</u>

झारखंड में सुखाड़ घोषणा के उपरांत सभी बैंक को अधिसूचना की प्रति 30-11-2018 को आरबीआई के संबन्धित circular के साथ एसएलबीसी द्वारा भेज दी गयी है। इस दिशा में बैंको द्वारा affected किसानों को relief measures प्रदान करने के लिए एक विशेष बैठक की जानी है ,एसएलबीसी के बारंबार आग्रह के बावजूद यह बैठक अभी तक नहीं हो पायी है। सभी घोषित जिलों के crop loss का प्रतिशत भी उपलब्ध करवाया नहीं गया है।इन विषयों के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग व कृषि विभाग , झारखंड सरकार को आग्रह भेजा जा चुका है। संबन्धित विभाग से आग्रह है की आंकड़े जल्द उपलब्ध करवाया जाय। **(ACTION: आपदा प्रबंधन विभाग व कृषि विभाग, राज्य सरकार)**

<u>एसएचजी महिलाओं के वित पोषण हेतु योजना</u>

एसएचजी महिलाओं को बीसी/सीएसपी के रूप में deploy करने का कार्य असंतोषजनक है। SHG पर गठित sub committee की पिछली बैठक में JSLPS के CEO श्री परितोष उपाध्याय द्वारा सभी बैंको से यह आग्रह किया गया कि वे SHG **महिलाओं** को अधिक से अधिक बीसी/सीएसपी के रूप में **deploy** करें। बैंक अन्य सहायता के लिए **JSLPS** के संबन्धित अधिकारियों से बात कर सकते है। **(ACTION: सभी बैंक)**

श्री पारितोष उपाध्याय ,सीईओ, जेएसएलपीएस ने सभी बैंको से 25000 लंबित आवेदनों को जल्द निष्पादित करने को कहा। उन्होने सूचित किया की 10000 आवेदन जल्द ही शाखाओं में भेज दिये जाएंगे। उन्होने सभी बैंक प्रमुख से एसएचजी के लंबित आवेदनों को अभियान चला कर निष्पादित करने का आग्रह किया। इस संबंध में उन्होने आग्रह किया कि राज्य के सभी शाखाओं को इस अभियान के लिए एक त्वरित निर्देश जारी करे। | **(ACTION: सभी बैंक)**
श्री दीप शंकर ने ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष से एसएचजी में नए स्वीकृत तथा Enhancement के लिए अलग अलग लक्ष्य दिए जाने का आग्रह किया। **(ACTION: JSLPS)**

श्री ए.के.पाढ़ी, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशनुसार SHG ग्रुप के प्रत्येक सदस्य का बैंक में बचत खाता का होना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज एवं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सदस्यता होनी चाहिए |

(Action :JSPLS/सभी बैंक /नाबार्ड)

वित्तीय समावेशन/प्रधानमंत्री जन धन योजना

श्री मदनेश मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग भारत सरकार ने कहा कि राज्य में प्रतिदीन 50 से कम transaction करने वाले BC की संख्या काफी अधिक है अर्थात कई BC का कार्य संतोषजनक नहीं है, जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है | कई जगहों पर कई बैंको के द्वारा BC की नियुक्ति में आ रही परेशानी को देखते हुए SLBC द्वारा SSAs के alottment का fresh exercise किये जाने की आवश्यकता पिछले तिमाही के बैठक में बताई थी जिसका कार्य कुछ जिलों में अभी भी अधूरा है।

(Action:SLBC,सभी संबंधित बैंक एवं LDMs)

श्री मदनेश मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्त सेवाएँ विभाग भारत सरकार ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन समिति का गठन किया जाना है जिसकी बैठक कम से कम छह: माह में एक बार होना है जिसमे राज्य में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हुए प्रगति की समीक्षा की जानी है | **(Action : SLBC एवं झारखण्ड सरकार)**

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य सरकार से लंबित पड़े certificate cases एवं SARFAESI cases के त्वरित निष्पादन का आग्रह किया गया | श्री बिनोद सिन्हा, OSD ,Finance ने सभी बैंकों को से यह आग्रह किया गया कि विभिन्न जिलों में SARFAESI के अंतर्गत physical possession के लिए जिलाधिकारियों के पास पड़े लंबित cases की जानकारी पूर्ण विवरण के साथ SLBC या सीधे उन्हे उपलब्ध करायी जाये जिसे राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीयों के साथ share किया जा सके| उन्होने बैंक के अधिकारियों को लगातार follow up का सुझाव दिया। श्री मदनेश मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग भारत सरकार ने कहा कि यह मुद्दा केंद्र स्तर पर भी चर्चा कि गई है और वहाँ भी पाया गया कि आवेदन जिलाधिकारियों के पास pending है और कई जगह DC/DM hearing के लिए बुलाते है ,जिनके कारण नीलामी प्रक्रिया प्रभावित होती है। उन्होने सभी एलडीएम को नियमित तौर पर जिलाधिकारियों से मिल कर लंबित आवेदन को तय सीमा में निष्पादित करवाने को कहा। श्री संजीव दयाल, महाप्रबंधक, आरबीआई ने एसएलबीसी को जिला स्तर पर आंकड़े संकलित कर सभी एलडीएम को देने कि बात कही जिससे कि एलडीएम जिला स्तर पर डीसी/डीएम से Follow Up कर सके। **(Action: डीसी/डीएम ,राज्य सरकार,SLBC एवं बैंक)**

PMEGP/PMAY/NULM

SLBC द्वारा सभी बैंको से इन schemes के तहत लंबित आवेदनों के अतिशीघ्र निष्पादन का आग्रह किया गया | SLBC के मुख्य प्रबंधक श्री दीप शंकर द्वारा सभी बैंको से यह आग्रह किया गया कि वर्तमान में चल रहे MSME outreach progaramme के तहत PMEGP आवेदनों की स्वीकृति से सम्बंधित आंकड़ों की हर स्तर पर close monitoring की जा रही ,उन्होने बताया कि सचिव, उद्योग, झारखंड सरकार ने इस संबंध में बैठक कर के MARGIN MONEY लक्ष्य को जल्द प्राप्त कर लेने को कहा है । श्री संजय कुमार , सहायक निदेशक ने बताया कि PMAY के अंतर्गत 75000 घर बनाने है। जिसमे उन्होने बताया कि घर की कीमत 7-8 लाख होगी जिसमे 1.50 लाख केंद्र एवं 1.00 लाख रुपए राज्य सरकार अनुदान दे रही है। बचे हुये राशि को लाभुक स्वयं निर्वहन करेंगे या बैंक से वित्तीय सहायता लेंगे। उन्होने बताया कि राज्य सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें बैंक के साथ Tripartite करने के फ़ारमैट कि चर्चा की। उन्होने बताया कि ऋण चुकाने से पूर्व लाभुक को घर का मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। उन्होने सभी बैंक से MoU कि sample प्रति देख कर MoU करने कि बात कही।उन्होने बताया कि घर से संबन्धित सभी कागजात बैंक को देगी। हालांकि उन्होने डिफ़ाल्ट के केस में बैंक द्वारा नीलामी कि प्रक्रिया मे एक शर्त जोड़ने की बात कही जिसके तहत अगर नीलामी प्रक्रिया में ULB या राज्य सरकार भाग लेगी तो प्रक्रिया में वरीयता ULB या राज्य सरकार को दी जाएगी। **(Action: सभी बैंक,राज्य सरकार)**

RSETI/FLCC

श्री पारितोष उपाध्याय ,सीईओ, जेएसएलपीएस ने कहा राज्य में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित RSETI के भवन निर्माण का कार्य संतोषजनक है परंतु SBI द्वारा RSETI के भवन निर्माण का असंतोषजनक है और इसमे प्रगति कि आवश्यकता है। उन्होने रामगढ RSETI के भवन निर्माण के संदर्भ में BOI को निर्णय जल्द ले लेने को कहा। उन्होने पिछले मीटिंग के क्रम में BOI के महाप्रबंधक श्री शंकर प्रसाद के द्वारा RSETI भवन के निर्माण की जिम्मेदारी extant guidelines के अनुसार सम्बंधित जिले में जो अग्रणी बैंक है, उनको दी जानी चाहिए को उद्धृत करते हुये कहा कि इस विषय पर जल्द निर्णय लेना आवश्यक है। BOI के महाप्रबंधक श्री शंकर प्रसाद ने इस मुद्दे को जल्द **Takeup** करने कि बात कही।श्री दीप शंकर ने बताया कि इकछुक **RSETI trainees** से ट्रेनिंग के उपरांत ही ऋण आवेदन ले कर संबन्धित बैंक भेज देने की बात की। श्री मदनेश मिश्रा ने स्थानीय स्तर के आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए **Potential Scheme** पर ही ट्रेनिंग दिए जाए।श्री अनिल कुमार,राज्य नोडल ,**RSETI** ने बताया की **RSETI** में गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर श्री मदनेश मिश्रा ने एक छोटी कमिटी बना कर स्टडी कर **RSETI** क्रेडिट लिंकेज कर प्रारूप में संशोधन करने को कहा। उन्होने इसे नए वित्तीय वर्ष से इसे लागू करने को कहा। **(Action: BOI, सभी बैंक , RSETI Directors, JSLPS)**

आर.बी.आई. के महाप्रबंधक श्री संजीव दयाल ने कहा कि आर.बी.आई. के निर्देशानुसार प्रत्येक एफ.एल.सी. के कार्य के लिए कौंसलर की नियुक्ति होनी चाहिए | बैंकों को सुनिश्चित करना है कि यह कार्य उनके अपने ही स्थाई कर्मचारी से ना लें | **(Action : सभी बैंक)**

विविध कार्यसूची

1. IOB से Mudra Promotion Campaign में हुए खर्च की राशी के लिए रु 77400 contribute किये जाने का आग्रह किया गया , जिसपर IOB के नियंत्रक प्रमुख को श्री मदनेश मिश्रा ने फरवरी अंत तक एसएलबीसी को भुगतान करने का निर्देश दिया । IOB के नियंत्रक प्रमुख ने 5 मार्च तक कार्यवाही हर हाल में कर लिए जाने का आश्वाशन दिया | **(Action: IOB)**

2.ROADMAP for villages having population between 2000 and 5000-राज्य में 2000 से 5000 तक की जनसंख्या वाले गाँव को बैंकिंग कवरेज सुनिश्चित करने के लिए एक Roadmap की आवश्यकता है। इसके लिए इस श्रेणी के सभी गाँव चिन्हित कर बैंकिंग सुविधा कवरेज सुनिश्चित करने हेतु सूची पूर्ण करने के लिए राज्य के सभी एलडीएम को लिखा जा चुका है। कुछ जिलों से सूची प्राप्त भी हो चुकी है।जिन जिलों में सूची लंबित है उनसे आग्रह है कि सूची से संबन्धित आंकड़े जल्द एसएलबीसी को अद्यतन कारवाई के लिए प्रेषित करे।**(Action: सभी LDMs)**

3. DFS द्वारा identified 440 centres पर BC की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में हुई चर्चा के दौरान VGB के द्वारा वैसे 11 centres जिनपर या तो connectivity issue अथवा किसी अन्य बैंक का SSA होने के कारण BC नियुक्त नहीं किया गया है , पर BC नियुक्त किये जाने की बात कही गयी | VGB के साथ साथ जामतारा, गढ़वा एवं लातेहार के LDMs से आग्रह किया गया कि यदि उन स्थानों पर कोई अन्य बैंक के BC कार्यरत हैं तो इसकी जानकारी SLBC को दी जाये |

(Action: VGB एवं LDMs- जामतारा, गढ़वा एवं लातेहार)

4. सभी LDMs से आग्रह किया गया कि राज्य के सभी 4178 SSA को पुनः नए सिरे से बैंको को allot किये जाने की आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में SLBC द्वारा जल्द ही दिए जाने वाले निर्देश के तहत उनसे इसपर कार्यवाही करने के लिए तैयार रहने को कहा गया | **(Action: सभी LDMs)**

5. SBI द्वारा पलामू में शेष 02 स्थानों Untari Road एवं Ramgarh में शाखा खोलने के लिए कहा गया | **(Action: SBI)**

6. MSME outreach programme के तहत राज्य में चिन्हित चार जिलों में प्रत्येक शुक्रवार को mega camp किये जा रहे है । सभा को बताया गया कि इस प्रोग्राम कि तिथि बढ़ा कर

28 फरवरी कर दिया गया है। श्री दीप शंकर ने बोकारो एवं खूंटी के एलडीएम को शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही पूर्बी सिंहभूम एवं गोड्डा को अच्छे कार्य के लिए बधाई दिया। श्री मदनेश मिश्रा ने लक्ष्य को समय सीमा में प्राप्त कर लेने को कहा। **GM, SLBC** श्री सहाय ने **Restructuring Process** में तेजी लाने को कहा। उन्होने एलडीएम को **correct** डाटा समय से पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया। खूंटी एवं बोकारो के एलडीएम ने समयसीमा में लक्ष्य प्राप्ति कर लेने का संकल्प दोहराया। सभा में चर्चा के दौरान PSB59MINS से जुड़े कुछ तथ्यों को आलोकित करने के लिए SIDBI के अधिकारी से बात करने को ढूंढा गया पर वो उपस्थित नहीं थे। **(Action: SLBC एवं सभी बैंक, SIDBI)**

7. **BLBC बैठक-CGM ,NABARD** श्री ए के पाढ़ी ने सभा को बताया कि कई ऐसे जिले है जहाँ प्रखण्ड स्तर पर होने वाले **BLBC** बैठक नहीं हो रही है। **GM, SLBC** श्री सहाय ने सभी **LDMs** को नियमित **BLBC** मीटिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।एलडीएम धनबाद ने यह मुद्दा उठाया की प्रखण्ड स्तर पर बैंक के शाखा प्रबन्धक बीएलबीसी बैठक को गंभीरता से नहीं लेते है। इस पर **GM, SLBC** श्री सहाय ने सभी बैंको को अपने शाखा प्रबन्धकों को अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने को कहा। श्री मदनेश मिश्रा ने बीएलबीसी बैठक को एक एसएलबीसी मीटिंग में एक **agenda** के रूप में शामिल करने को कहा।उन्होने एक फ़ारमैट तैयार कर जिसमे की प्रखण्ड वार बैठक की तिथि, प्रखण्ड में कुल बैंक शाखाओं की संख्या, उपस्थित बैंक की संख्या को संलग्न करने को कहा। सभी एलडीएम को हर तिमाही अपने सभी प्रखण्ड में हुये बीएलबीसी बैठक की जानकारी एसएलबीसी को समयसीमा में उपलब्ध करनी है। **(Action:SLBC,सभी बैंक एवं LDMs)**

8. Branch Network - बारंबार यह देखा गया है कि बैंक अपने शाखाओं की संख्या में परिवर्तन ले आते है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 31.03.2019 को जो शाखाओं के आंकड़े होंगे , वे **BASE DATA** के रूप में कार्य करेंगे।बैंक ऑफ इंडिया के घटते एटीएम पर श्री मदनेश मिश्रा ने चिंता व्यक्त की। उन्होने बैंक ऑफ इंडिया ,रांची अंचल के आंचलिक प्रबन्धक श्री तेजेस्वर पटनायक से **defaulter service provider** पर उचित कदम उठाने को कहा।

9. Axis Bank ने बैठक के अगले दिन pos से संबन्धित सही आंकड़े एसएलबीसी को प्रेषित करने की बात कही। (Action: Axis Bank)

10. कैश की समस्या- श्री मदनेश मिश्रा, संयुक्त सचिव ने आरबीआई, सभी बैंक एवं एलडीएम से आने वाले समय में कैश की किल्लत की समस्या से निजात पाने का प्रबंधन करने को कहा।

11. बैंकों को प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र- राज्य में बैंकों के Overall प्रदर्शन के आधार पर दो

सर्वश्रेष्ठ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया। आने वाली हर बैठक में यह प्रोत्साहन का कार्यक्रम जारी रहेगा।

12. एलडीएम को सम्मान -RBI के निर्देशानुसार पिछली तिमाही में सेवानिवृत हुए दो एलडीएम श्री फाल्गुनी राय (पूर्वी सिंहभूम) एवं श्री दिलीप मजूमदार(बोकारो) को उनके एलडीएम के रूप में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

अंत में SLBC,JHARKHANDके DGM श्री विंसेंट लकरा ने उपस्थित गणमान्य विशिष्ट अतिथियों एवं उपस्थित सभी लोगों को 66वीं SLBC को सुचारु संचालन के लिए धन्यवाद दिया तथा सभी हितधारकों से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं में बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया ताकि राज्य का समुचित हो सके।

(विन्सेंट लकड़ा)
उप महाप्रबंधक, रा.स्त.बै.स.

State Level Banker Committee BOI Jharkhand

LIST OF PARTICIPANTS IN 66th STATE LEVEL BANKERS' COMMITTEE, JHARKHAND
(MEETING HELD ON 15.02.2019)

S.N	NAME OF PARTICIPANTS	DESINGNATION	BANK/DEPARTMENT	CONTACT NO.
1	Sri M. K. Mishra	Joint Secretary	Department of Financial Services	
2	Sri Satendra Singh	Secretary	Department of Planning Cum Finance	
3	Sri Sanjiv Dayal	General Manager OIC	Reserve Bank of India	
4	Sri A K Padhi	Chief General Manager	NABARD	
5	Sri Shanker Prasad	General Manager	Bank of India	
6	Sri A K Sahu	General Manager	State Bank of India	
7	Sri C S Sahay	General Manager	SLBC Jharkhand	
8	Sri Vincent Lakra	Dy General Manager	SLBC Jharkhand	
9	Sri Paritosh Upadhyay	CEO	Rural Development Dept.	
10	Sri S B Jena	Allahabad Bank	Field General Manager	
11	Sri Atul Kumar	Union Bank	Field General Manager	
12	Sri Binod Sinha	OSD		
13	Sri Manoj Kumar	Chief Manager	Vijaya Bank	7234842571
14	Sri Sanjiv Kumar	Sr Manager	Punjab & Sindh Bank	8083139213
15	Sri Amit Kumar	Chief Manager	Dena Bank	9152940875
16	Sri B N Kujur	Sr. Manager	Bank of Baroda	9472755230
17	Sri Abhishek Kumar	Sr. Manager	Bank of Maharshtra	8927661482
18	Sri Prakash Chandra	Dy. General Manager	NABARD	9437487632
19	Sri Jitendra Kumar Singh	Dy. General Manager	IDBI Bank	9801052713
20	Sri Raj Kishor Srivastava	Chief Manager	Oriental Bank of Commerce	8057228000
21	Sri Deepak Kumar Prasad	Sr. Manager	Oriental Bank of Commerce	9955991580
22	Sri Sanjay Kr. Sinha	Asst General Manager	State Bank of India	9065516672
23	Sri Nandan Kumar	Chief Manager	State Bank of India	9771487986
24	Sri Tejeswer Patnaik	Zonal Manager	Bank of India	9262296296
25	Sri S K Kukreja	Dy. Circle Head	Punjab National Bank	9599043428
26	Sri K P Mandal	Dy. Regional Head	Union Bank	8407004125
27	Sri Sanjib Sarkar	Chairman	Jharkhand Gramin Bank	9915599979
28	Sri Rajiv Nayan Sinha	Chief Manager	Jharkhand Gramin Bank	9431757563
29	Sri S K Sinha	Dy General Manager	United Bank of India	9934011359
30	Sri Vivek Kr. Sharma	Chief Manager	United Bank of India	9339464570
31	Sri Sunil V. Zode	Chairman	Vananchal Gramin Bank	9922957870
32	Smt Anita Ekka	Asst General Manager	Canara Bank	6200827424
33	Sri Manoj Kumar Sharma	Chief Manager	Indian Overseas Bank	9431289006
34	Sri Surendra Kr Das	Regional Manager	Syndicate Bank	7544012320
35	Sri Binod Kumar Ram	Under Secretary	Dept. Of Welfare	9431583478
36	Smt Preety Ekka	Asst Manager	Indian Overseas Bank	8770678184
37	Sri Bindeshwar Das	DDS	Dept. Of Industry	9431783653
38	Sri Shishir Kr Sinha	Joint Secretary	Dept. Of Agriculture	7903163655
39	Sri Iqbal Alam Ansari	Special Secretary	Dept. Of Home	9431375602
40	Sri Anil Kumar Meelu	Regional Manager	Central Bank of India	9570900446
41	Sri Awadhesh Kr Choudhary	Lead District Manager	Garhwa	9934363709
42	Sri Kishore Tirkey	Lead District Manager	Palamu	9934363710
43	Sri S L Baitha	Lead District Manager	Jamtara	9771462495
44	Sri C S D Paan	Lead District Manager	Latehar	7781011677
45	Sri R S K Sinha	Lead District Manager	Deoghar	9771435410
46	Sri Rajesh Kumar Diwedi	Lead District Manager	Dumka	7295921636
47	Sri Raman Kumar Sinha	Lead District Manager	Godda	9006642698
48	Sri Vikash Kumar Singh	Lead District Manager	Pakur	9771438410
49	Sri Ram Das Rajak	Lead District Manager	Sahebganj	9771438409
50	Sri Dhiraj Kr Horo	State Program Manager	JSLPS	8969170434
51	Sri Anil Kumar	State Nodal Officer	JSLPS	9431901016
52	Sri Shushil Kumar	General Manager	JSCB	9431184663
53	Sri Hemant Kr Pandey	Asst. General Manager	JSCB	9431595810
54	Sri Ch. Sriniwasa Sastry	Zonal Manager	Andhra Bank	7070992529
55	Sri Amrendra Kumar	Sr. Manager	HUDCO	9431815999
56	Sri Ajith Kumar	Regional Chief	HUDCO	9969293461
57	Sri Rahul Dwidedi	Zonal Manager	Utkarsh Small Finance Bank	8173001178
58	Sri Vikash Kumar	Zonal Head	Utkarsh Small Finance Bank	7091091451
59	Sri Sudhanwa Mishra	Lead District Manager	Khunti	9931175578
60	Sri S K Sai	Lead District Manager	Gumla	9113361788
61	Sri Srikant Kumar	Lead District Manager	Simdega	9798967181
62	Sri Sanjay Kr Sinha	Lead District Manager	Ranchi	9905826908
63	Sri Ravi Kant Sinha	Lead District Manager	Lohardaga	9470116528

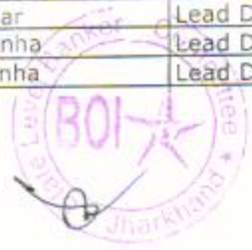

S.N	NAME OF PARTICIPANTS	DESINGNATION	BANK/DEPARTMENT	CONTACT NO.
64	Sri Anil Kumar	Lead District Manager	East Singhbhum	9431182446
65	Sri Fudan Murmu	Lead District Manager	West Singhbhum	7004720085
66	Sri S N Mohanty	Lead District Manager	Seraikela	9102956616
67	Sri Ravindra Kumar Singh	Lead District Manager	Giridih	8340133328
68	Sri Asharfi Paswan	Lead District Manager	Bokaro	8809241069
69	Sri Shatrunjay Prasad	Lead District Manager	Ramghar	9472742683
70	Sri Amit Kumar	Lead District Manager	Dhanbad	8298715715
71	Sri M K Das	Lead District Manager	Chatra	9931540333
72	Sri Sudhir Kumar Das	Lead District Manager	Hazaribagh	6201095571
73	Smt Rani Bala Sethi	Nodal Officer	Axis Bank	9905102122
74	Sri Sudhanshu Kumar	AVP & Nodal Officer	Axis Bank	8877969009
75	Sri Aditya Saraf	AVP	Bandhan Bank	8877969009
76	Sri Vivek Pant	Regional Head	ICICI Bank	7033594179
77	Sri Rakesh Kumar	Chief Manager	ICICI Bank	9771438768
78	Sri Vikash Kumar	Dy Director	Dept. Of Agriculture	8210977085
79	Sri Sabbir Akhter	Regional Head	ICICI Bank	9771499046
80	Sri Rabish Kumar	Asst Manager	Karur Vysya Bank	8789949172
81	Sri Himanshu Jaiswal	Manager	Federal Bank	8527486963
82	Sri R Hansdah	Asst. Manager	Corporation Bank	9470990532
83	Sri Akshay Kumar Sharma	Associate Executive	Jammu & Kamshmir Bank	7006720107
84	Sri Kali Charan Das	Lead District Manager	Koderma	9430357800
85	Ms Baishali Chakraborty	Asst. Manager	South Indian Bank	9903450699
86	Md Rustam	Asst Director II	Khadi & VI Commission	9507676351
87	Sri Prem Trigunait	Regional Operation Manager	Jana Bank	7280001724
88	Sri Alok	Dy Zonal Head	UCO Bank	9572629227
89	Sri Gautam Patra	Zonal head	UCO Bank	9819466976
90	Sri Sanjay Kumar	Asst Director	Urban Dev and Housing Dept	8651514821
91	Sri Mukseh Kumar Jha	Specialist	Urban Dev and Housing Dept	9199534281
92	Sri Shashi Mohan	DAO	Office of Registrar Co. Society	9934499942
93	Sri Rajesh Kumar Singh	Asst Manager	Union Bank	9431572972
94	Sri Manoj Kumar	Sr. Manager	Allahabad Bank	7897785386
95	Sri Manitesh Kumar	Sr. Manager	HDFC Bank	9334612421
96	Sri Abhishek Verma	Cluster Head	Yes Bank	7064800824
97	Sri Subhash Kumar	Regional Head	Indusind Bank	7260811600
98	Sri Ram Sagar Pandey	Cluster Head	Bandhan Bank	9102675110
99	Sri Kamal Choudhary	Kotak Mahindra Bank	Manager	9386802023
100	Sri Kiran Mishra	Kotak Mahindra Bank	Chief Manager	9709000208
101	Sri Bibhaw Kumar	Manager	Bank of India	9034846704
102	Sri Kishore Kumar	Branch Head	LVB	9308457750